



रीवा इंदौर के बीच 72 सीटर हवाई सेवा शुरू

इंदौर: मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही विन्ध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा के रूप में एक और सौगात मिली है। एटीआर विमान ने सोमवार को यात्रियों को लेकर रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान भरी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में, रीवा इंदौर विमान सेवा की शुरुआत हो गई। रीवा से इंदौर हवाई सेवा विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा और विकास, व्यापार और पर्यटन के अवसरों को सशक्त बनाएगा। विन्ध्य क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, रीवा एयरपोर्ट से इंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस 72सीटर फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ट्रेन या बस से करीब घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो सकेगी। पहले ही दिन इस उड़ान की सभी सीटें फुल रहीं, जिससे साफ है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी मांग है।

कड़ा के की ठंड से स्कूल बंद

उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं क्रिसमस नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में स्कूल छुट्टियों को लेकर आधिकारिक घोषणाएं सामने आने लगी हैं। कुछ राज्यों ने लंबी विंटर वेकेशन का ऐलान किया है, तो कुछ ने परंपरा से हटकर स्कूल खुले रखने का फैसला लिया है। दिल्ली में जहां क्रिसमस की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं यूपी में इस बार परंपरा टूटने जा रही है। दिल्ली में दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 25 दिसंबर को रिस्ट्रिक्टेड होलिडे घोषित किया गया है, यानी स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। अधिकतर स्कूलों के पूरी तरह बंद रहने की संभावना है।

कोडीन सिरप मामले में सीएम योगी का सपा पर हमला, विधानसभा में तीखी बहस

लखनऊ: कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा), पर तीखा हमला बोला। चर्चा के दौरान उन्होंने इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों और उनके कथित राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में बर्खास्त पुलिसकर्मी आलोक भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी अमित सिपाही का समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है और उसकी फोटो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मौजूद है, जिसे उन्होंने सदन में दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में माफिया से किसके संबंध हैं, यह प्रदेश की जनता जानती है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल के भी सपा से संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुभम जायसवाल, अमित यादव का कारोबारी साझेदार है, जो वाराणसी कैंट से सपा



का प्रत्याशी रह चुका है। इसके अलावा उन्होंने मिलिंद यादव का भी नाम लिया और कहा कि वह शुभम जायसवाल का करीबी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, मिलिंद यादव का फोन नंबर एक फर्म के जीएसटी पंजीकरण में दर्ज है।

इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने लगातार विरोध दर्ज कराया और सदन में हंगामा होता रहा। शोर-शराबे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा

नहीं जाएगा।

गौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नियम ५ के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी पर चर्चा की मांग की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का पहला राज्य है,

जहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSD) ने अब तक पम्प दुकानों पर छापेमारी की है, जिनमें से कम्प्लेंटों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है, हालांकि राज्य के बाहर इसके दुरुपयोग से मौत के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ के कई थोक विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक एक हजार से अधिक सिरप नमूनों की जांच की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग नशे और मनोरंजन के लिए कफ सिरप का दुरुपयोग करते हैं, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और एक भी अपराधी बचने नहीं दिया जाएगा।

AAP का आरोप: आदिवासी फंड से पीएम मोदी की रैलियों पर करोड़ों खर्च

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदिवासी विकास निधि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि गुजरात में प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी कार्यक्रमों के लिए आदिवासी फंड से करोड़ों रुपये खर्च किए गए।

AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए निर्धारित फंड से करीब ५ करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे जुड़े कार्यक्रमों में सुविधाएं जुटाने पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था।

अनुराग ढांडा ने खर्चों का विस्तृत ब्योरा देते हुए बताया कि डेडियापाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपये का पंडाल, करोड़ रुपये का गुंबद, ५ करोड़ रुपये का मंच, ४ करोड़ रुपये चाय-नाश्ते पर, २ करोड़ रुपये लोगों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था पर और ४ करोड़ रुपये शौचालय व साफ-सफाई पर खर्च किए गए।

इस दौरान AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत सेंट्रल विस्टा में बन रहे प्रधानमंत्री आवास के खर्च के बारे में जानकारी मांगी गई, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया गया। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से जुड़े



खर्चों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया गया, जहां किसी तरह की सुरक्षा आपत्ति नहीं जताई गई।

AAP सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग हजार बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उनके अनुसार, बच्चों के पोषण, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के लिए निर्धारित फंड को प्रधानमंत्री की

रैलियों में खर्च किया गया।

संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधायकों ने सरकारी अधिकारियों से कुपोषण दूर करने के लिए फंड की मांग की, तो जवाब मिला कि सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वही पैसा प्रधानमंत्री की रैलियों पर खर्च किया जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री को हो सकती है जेल?



Ali Aadil Khan
Editor

किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए IPC की धारा 354 और

अली अदिल खान

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की तबीयत खराबी की खबरें और Visuals सामने आते रहे हैं, लेकिन वो इतने बीमार हैं की महिलाओं के हिजाब खींचने लग जाएंगे ऐसा प्रदेश और मुल्क की अवाम की सोच से भी परे की बात है. सड़क के गुंडे मवाली भी इस तरह की हरकत करते वक़्त लोगों की नज़र से बचने की कोशिश करते हैं. और यहाँ यह हरकत स्टाफ , जनता और मीडिया के सामने किये जाने को कोई बीमारी ही कहा जाएगा, अब चाहे वो शारीरिक हो या वैचारिक. अब इस घिनौने घटना कर्म के तीन हिस्से हैं ,अगर यह शारीरिक बीमारी का असर है उनको तुरंत रिटायरमेंट लेना चाहिए, वैचारिक बीमारी का असर है टोपी लगाने की साज़िश सियासत से बाहर रहना चाहिए और अगर यह एक महिला को अपमानित करने की नीयत से किया गया था तो इसपर उनको सजा के लिए तैयार

रहना चाहिए .

इस तरह के मामले में सबसे प्रत्यक्ष और प्रमुख धारा है। ‘शील भंग’ (Modesty Outraging) में महिला के शरीर या वस्त्रों के साथ ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है. क्योंकि किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए IPC की धारा 354 और/या धारा 354B के तहत एक साल से लेकर सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. हालाँकि यह बात तय है कि जब तक वो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के सहभागी हैं तब तक तो वो सरकार की नज़र में दूध के धुले हैं लेकिन जैसे ही समर्थन वापस लेते हैं तुरंत उनके खिलाफ इसी केस में PIL डालकर झड़ूक्रहो सकती है. लेकिन उनकी बीमारी भी इतनी समझदार है कि कोई ऐसा काम नहीं कराएगी जिससे वो सत्ता से बाहर आजायें. अब वो हर हाल में केंद्र सरकार के समर्थन में रहकर ही अपना

समय पूरा करना मुनासिब समझेंगे. नितीश कुमार जो जन सेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा की गई यह घटिया हरकत सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि यह संवैधानिक मर्यादा, महिला सम्मान और व्यक्तिगत आज़ादी पर गंभीर चोट है जो सरकार की संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर के हिजाब को सार्वजनिक मंच पर हटाना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर Depty CM उनको पीछे से न रोके होते तो शायद वो पूरा हिजाब ही खींच सकते थे. हालाँकि उनकी बाँड़ी लैंग्वेज से उनके मानसिक असुंतलन का आभास तो हो रहा था. और इसी ग्राउंड पर इनको माफ़ी मिल सकती है अन्यथा सीधा जेल का प्रावधान है, अगर अदालत चाहे तो . बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की मंशा चाहे कुछ भी रही हो, किन्तु किसी महिला की सहमति के बिना उसके पहनावे को छूना वह भी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठकर, न सिर्फ़ अमानवीय

और अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक आचरण और देश के क़ानून के भी ख़िलाफ़ है। इस घटना के बाद अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि महिलाओं का सम्मान कोई नारा नहीं, बल्कि उनका बुनियादी अधिकार है। और धार्मिक पहचान चाहे वह किसी भी मज़हब की हो निजी मामला है, राजकीय सरकारी मंच के उच्चतम पद पर बैठकर ऐसा नफरती प्रदर्शन शायद देश की पहली घटना है। सवाल सिर्फ़ एक नेता के व्यवहार का नहीं, सवाल उस सोच और मानसिकता का है जो सत्ता में बैठकर व्यक्तिगत सीमाओं को लांघने को अपना अधिकार मान बैठी है। आज ज़रूरत इस तरह की घटनाओं पर सफ़ाई देने की नहीं बल्कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और सार्वजनिक माफ़ी को सुनिश्चित करने की है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता क़ानूनी दायरे में रहकर ही सम्मानीय हो सकती है, किसी नागरिक की गरिमा, सम्मान और अधिकारों से बढ़कर नहीं।

मध्यप्रदेश विधान सभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र विकास को समर्पित प्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित करने का आयश्वासन

एल.एस. हरदेनिया

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र क़र्र दिसंबर को आयोजित किया गया। यह सत्र दो उद्देश्यों से बुलाया गया था। पहला था मध्यप्रदेश विधानसभा का छह वर्ष पूर्ण होना और दूसरा ख़ूब तक मध्यप्रदेश के विकास पर एक विजन डायलॉग पर चर्चा करना। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजन डायलॉग सत्ताधारी विधायकों विचारों पर आधारित तो होगा ही परंतु प्रतिपक्ष के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की इच्छा प्रकट की और मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे रखे।

ख़ास बात यह थी कि विशेष अधिवेशन में भाषण देने वाले क़ विधायक सत्ताधारी दल के थे और क़ प्रतिपक्ष के। दोनों पक्षों के विधायकों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। विधानसभा में क़-५५ से लेकर अभी तक राज्य के जितने मुख्यमंत्री रहे, उनके योगदान पर विशेष चर्चा की गई। इन मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस के रविशंकर शुक्ल, मंडलोई, कैलाशनाथकाटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविन्द नारायण सिंह आदि शामिल थे। भाजपा (पूर्व में जनसंघ) के जो

मुख्यमंत्री बने उनमें कैलाश जोशी, सुन्दरलाल पटवा, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल थे। इसके अतिरिक्त अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा आदि मुख्यमंत्रियों के योगदान का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा कक्ष में प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी मध्यप्रदेश के विकास और विधानसभा के इतिहास पर केन्द्रित थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं के दो वर्ष के कार्यकाल की चर्चा की और प्रदेश की जनता से कहा कि वे बताएं कि इन दो वर्षों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इस समय मध्यप्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर दो वर्ष होने पर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ तो बहुत ही अनोखे हैं। जैसे स्पेशल क्विज आयोजित करना। दूसरा अनोखा कार्य था मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र। इस सत्र के माध्यम से आज के मध्यप्रदेश विधानसभा का इतिहास दिया गया है। मध्यप्रदेश का मानचित्र भी जारी किया गया जिसमें इंदौर, भोपाल, भिंड प्रदेश, मालवा और महाकौशल छत्तीसगढ़ भी शामिल था, जिस समय मध्यप्रदेश बना था। आज छत्तीसगढ़ हमारे प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इस क्विज के माध्यम से कुछ जानकारी देना का तरीका अपनाया गया था। साधारणतः क्विज स्कूल और

कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए खेला जाता है और ऐसा यह पहली बार है कि क्विज आम जनता के बीच में भी खेला गया है। इस क्विज को आम लोगों के बीच में प्रचारित करने के लिए समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपे हैं। दूसरी इस क्विज से यह जानकारी ली गई है कि मध्यप्रदेश कब बना था? कौन उसके पहले राज्यपाल थे? कौन उसके पहले मुख्यमंत्री थे? कौन विधानसभा के सदस्य थे? आदि क्विज के माध्यम से आम जनता से इस तरह की जानकारी मांगी गई। इसका उद्देश्य साफ़ है कि लोगों को यह पता लगे कि पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। जो सिर्फ़ एक महीने मुख्यमंत्री रहे और जिनकी अचानक दिल्ली में हृदयगति रुकने से मृत्यु हो गई। फिर यह बताया गया है कि मध्यप्रदेश का राज्यपाल कौन थे? फिर बताया जाता है कि डॉ. पट्टाभिषीतारमैया। डॉ. पट्टाभिषीतारमैया ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाषचंद्र बोस के खिलाफ़ चुनाव लड़ा था। वो चुनाव में हार गए थे। जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि डॉ. पट्टाभिषीतारमैया की हार मेरी हार है। डॉ. पट्टाभिषीतारमैया का बहुत बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने कांग्रेस की अधिकृत जीवनी लिखी है अर्थात् कांग्रेस का इतिहास लिखा है। इसके साथ ही विधानसभा भवन में एक

प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें से लेकर आज तक मध्यप्रदेश की विकास यात्रा को दिखाया गया है। जिसको काफी लोग देखने आए और मध्यप्रदेश के इतिहास को समझे। मिंटों हाल का भी अपना एक इतिहास है। भोपाल इसलिए ही चुना गया कि मिंटों हाल के समान एक बड़ा कक्ष मध्यप्रदेश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। मिंटो हाल को पहली विधानसभा के रूप में उपयोग किया गया था। मिंटो हाल तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल जब भोपाल आए तो उनके सम्मान में बनाया गया था। इस कक्ष में इतनी जगह थी कि पहली विधानसभा का अधिवेशन इसमें किया गया था। प्रथम अधिवेशन में गवर्नर ने अपने उद्घाटन भाषण में यह दावा किया था कि नए राज्यों का निर्माण अत्यधिक शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। गवर्नर के इस भाषण को चुनौती दी थी विंध्य प्रदेश के आने वाले विधायक सी.पी. तिवारी ने। उन्होंने कहा कि यह बात गलत है। तथ्य यह है कि नए राज्यों के बनने के साथ ही बहुत खून खराबा हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग नाराज थे। इतना समृद्ध राज्य जो भाषा के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से आगे होने के बाद भी महाराष्ट्र को एक पृथक राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। बाम्बेप्रेसिडेन्सी में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल रहे। ज्यों ही रिपोर्ट जाहिर हुई तब महाराष्ट्र और खासकर बंबई में भयंकर विरोध प्रारंभ हो गया। यहां तक कि इस विरोध को दबाने

के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। यहां तक कि होटल में बैठे लोगों पर भी गोलियां चलीं। कई स्थानों पर गोलियां चलीं। इसलिए सीपी तिवारी ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि राज्यों का निर्माण बिना खून-खराबे के हो रहा है। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनमें मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाईं। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, उसे अभ्युदय के नाम से मुख्यमंत्री के द्वारा और स्वयं उनके मंत्रियों द्वारा बताया गया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लगभग सभी अखबारों को इंटरव्यू दिए और स्वयं अपने द्वारा किए गए विकास से खासकर उद्योगों में निवेश को लोगों को समझाया। बहुत सारी सूचनाएं दी गईं। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे पूरे प्रदेश में जाकर अपने-अपने जिलों में जहां वो रहते हैं और उन्हें जिस जिले का प्रभारी बनाया गया है वहां जाकर बताएं कि उन जिलों में क्या-क्या कार्य हुए हैं। मंत्रियों के अलावा विधानसभा के विधायकों और पार्टी के नेताओं को भी आदेश दिया गया कि वे रात गांव में गुजारे। उनके दावों को कांग्रेस ने लगभग गलत बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये सब गुब्बारे हैं जिन्हें फोड़ा जा सकता है। यह एक संयोग है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने कार्यकाल के दो साल इसी माह पूरे किए हैं।

Russia urges IAEA to keep its inspection into Iranian nuclear programme within neutral, apolitical framework

Cairo: Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov has urged UN’s nuclear watchdog chief, Rafel Grossi, to keep the International Atomic Energy Agency’s (IAEA) investigation into Iran’s nuclear programme within a balanced, neutral, non-political, and impartial framework, saying any renewed cooperation must be on mutually acceptable terms.

“We call on IAEA Director General Grossi, who is pushing to restore contacts with Tehran, to strictly adhere to the founding mission of the IAEA Secretariat,” Lavrov told the media in Cairo on Friday, reports TASS today.

“This includes the neutral, unbiased, and professional nature of assessments and the broader activities of this organisation,” Lavrov added.

Iran and the International Atomic Energy Agency (IAEA) have found each other at loggerheads in the past six months, before reaching an uneasy technical understanding in the Egyptian capital in September, after Egypt mediated a deal between Tehran and the IAEA, geared towards the gradual restoration of the UN nuclear watchdog’s access for inspecting its nuclear sites.

Following the reimposition of all pre-2015 international sanctions on Tehran back in September, Iranian Foreign



Minister Abbas Araghchi deploring the move, claimed that the US and the E-3 nations had “killed” the Cairo nuclear agreement through its hostile actions.

Lavrov, commenting on the recent tussle between Tehran and Vienna, said that Iran could not be expected to resume full cooperation on fair terms, while being cornered into a wall and being bombed with economic and political sanctions.

“Moscow backs efforts to resume talks between Iran and the IAEA, but only on a fair basis that Tehran views as balanced and consistent with the agency’s mandate,” he added.

The IAEA Board of Governors adopted a Western-backed resolution last month, urging Iran to provide full access and information about its atomic research project, with diplomats noting that the measure was passed by a massive margin, with 19 votes in favour, 12 abstentions, and only three against, with Russia, China, and Niger voting against it.

The resolution called on Iran to allow verification of its enriched uranium stockpile and inspections at sites damaged by US and Israeli airstrikes in June.

Accusing the US of trying to achieve through diplomacy what it could not

gain by military force, he criticised Washington’s demands, stating “They want us to accept zero enrichment and limits on our defence capabilities, adding “This is not negotiation.

This is dictation” Trump had previously said that Iran could avoid its past mistakes and further tensions by reaching a deal, adding that any attempt to revive its nuclear programme without an agreement would prompt further US action, remarking that it missed a chance earlier though the table remains open.

Iran denies seeking nuclear weapons and claims its nuclear programme is for peaceful purposes, though this has been heavily disputed by the US, Israel, EU, and NATO states, citing Tehran’s extremely high levels of uranium enrichment which far exceed levels needed for civilian use.

Also refusing to hold talks with Washington over Tehran’s nuclear programme, Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in a flat-out rejection of US demands for curbing uranium enrichment and its rebuilding its missile capabilities, mocked US President Donald Trump, saying that dealing with him was beneath the dignity of the Islamic Republic.

NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

US Forces Seize Second Oil Tanker Near Venezuela

Washington: US Secretary of Homeland Security Kristi Noem said on Saturday that US forces seized another oil tanker off the coast of Venezuela earlier in the day.

According to Noem, the US Coast Guard, with support from the Department of Defense, intercepted the tanker in a pre-dawn operation on December 20. She said the vessel had last docked in Venezuela.

This marks the second such seizure in recent weeks. On December 10, US forces detained an-



other oil tanker near Venezuela, a move that the Venezuelan government condemned as “theft” and a violation of international law, according to Xinhua News Agency.

US President Donald Trump has announced

a blockade of oil tankers subject to US sanctions that are traveling to and from Venezuela. He stated that the United States would continue seizing vessels as part of this policy.

In a post on social

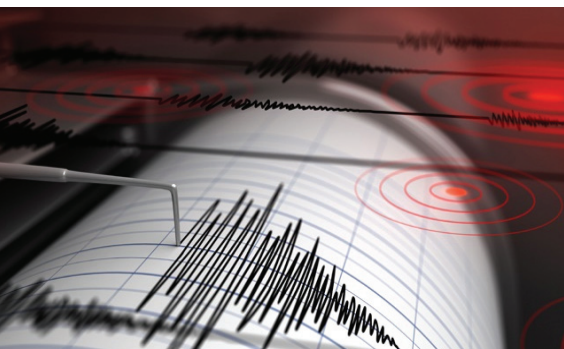
media, Trump said the blockade was intended to pressure Venezuela to return oil and other assets that he claims were taken from the United States.

The Venezuelan government strongly rejected the announcement, calling it a “reckless and serious threat” that violates international law, free trade principles, and freedom of navigation. In a statement, Venezuelan authorities accused the United States of attempting to seize resources that belong to Venezuela.

5.5-magnitude quake hits off Japan's Aomori Prefecture

Tokyo: An earthquake with a preliminary magnitude of 5.5 struck off Aomori Prefecture in northern Japan on Sunday, the country’s weather agency said.

The temblor occurred at 10:29 a.m. local time off Aomori’s Pacific coast at a depth of 50 km, measuring 4 on Japan’s seismic scale of 7,



said the Japan Meteorological Agency (JMA).

The quake’s epicenter

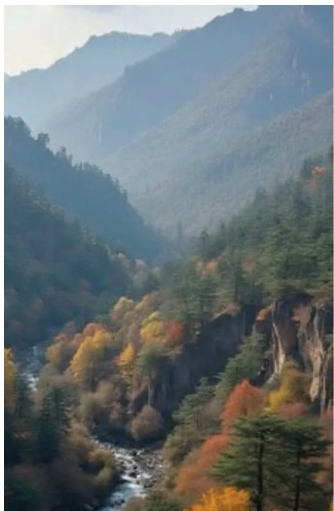
was located at a latitude of 40.7 degrees north and a longitude of 142.3

degrees east. No tsunami advisory was issued. Although a week-long alert regarding the increased risk of another strong earthquake was lifted on Monday after a 7.5-magnitude temblor struck northern and northeastern Japan on Dec. 8, JMA officials urged people to remain cautious.

अरावली को लेकर फैलाई जा रही है गलत जानकारी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और कथित अफवाहों के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की जा रही है और इससे भ्रम फैलाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से पढ़ा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अरावली को हरा-भरा और संरक्षित रखने पर जोर दिया है।



भूपेंद्र यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा प् में यह स्पष्ट किया गया है कि अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने केवल खनन से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति के गठन का निर्देश दिया है। मीटर ऊंचाई को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दावा गलत है कि संरक्षण का नियम पहाड़ी की चोटी से लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संरक्षण का आधार पहाड़ी की नींव से माना जाता है, भले ही वह जमीन के नीचे से शुरू हो। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में फैली हुई है। इसमें वन्यजीव अभयारण्य और चार बाघ अभयारण्य शामिल हैं, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि अरावली से जुड़ा कानूनी मामला सुप्रीम कोर्ट में 1995 से लंबित है और सरकार अरावली में खनन के खिलाफ सख्त नियमों का समर्थन करती रही है।

इस बीच, इंडियन फॉरिस्ट सर्वे ने चेतावनी दी है कि अरावली की करीब पहाड़ियों में हो रही खनन गतिविधियां इसके क्षरण का बड़ा कारण बन रही हैं। वहीं, सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी (CEC) ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को जरूरी बताया है।

यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम

अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान

लखनऊ: अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिए करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए किया जाएगा। इस निर्णय को ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और उनसे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रस्ताव रखा गया है।



अनुपूरक बजट के अंतर्गत सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण

पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।

इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी। वहीं, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से पंचायतों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को स्थान मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

गैंगस्टर एक्ट में चयनात्मक कार्रवाई से कमजोर हो रहा कानून का राज: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असाમાजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि चयनात्मक जांच और अभियोजन कानून के शासन के विपरीत हैं और इससे शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होता है।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और डीएम-एसएसपी की संयुक्त बैठक में आवश्यक संतोष दर्ज किए बिना ही कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि उनके निर्णय न्याय प्रणाली की दिशा तय करते हैं और इतिहास उन्हें दर्ज भी करता है।

हाईकोर्ट ने गृह विभाग को आगाह करते हुए कहा कि चयनात्मक जांच और अभियोजन कानून के राज को कमजोर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संगठित और प्रभावशाली अपराधी अक्सर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अभियोजन तंत्र उन्हें प्रभावी ढंग से चुनौती देने में विफल रहता है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट

प्रणाली लागू है, वहां गैंग चार्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में जिलाधिकारी को शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि गैर-कमिश्नरेट जिलों में डीएम और एसएसपी की संयुक्त बैठक अनिवार्य है। कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियम के नियम का उल्लंघन बताया।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नवंबर की अधिसूचना के तहत पुलिस आयुक्तों को जिलाधिकारी के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने सवाल उठाया कि कमिश्नरेट जिलों में पुलिस को इतने व्यापक अधिकार क्यों दिए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में वही प्रक्रिया संयुक्त प्रशासनिक निगरानी में होती है।

जन सुनवाई में सख्त दिखे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लापरवाही पर राजस्व कर्मचारी निलंबित

मुजफ्फरपुर: उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में जन सुनवाई के दौरान जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग भूमि विवाद और राजस्व संबंधी शिकायतें लेकर पहुंचे।

शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुशहरी अंचल के सतपुरा में पदस्थ राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल उसे निलंबित करने और जिले से बाहर स्थानांतरण का

निर्देश दिया।

डिप्टी सीएम ने जिले में वर्षों से चली आ रही भूमि मामलों की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों को फटकार लगाई और एक अंचलाधिकारी पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप की जांच के आदेश दिए।

विजय सिन्हा ने कहा कि यदि सरकारी जमीन में गलत तरीके से दाखिल-खारिज, परिमार्जन या किसी भी तरह की हेराफेरी पाई गई तो कार्रवाई केवल बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहेगी।

दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी निजी नाम से कराने वालों की जानकारी देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और ई-मापी से जुड़े लंबित मामलों का निष्पादन अगले 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार जन सुनवाई में आने की जरूरत न पड़े।

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड लुथरा ब्रदर्स की पुलिस हिरासत बढ़ाई

नई दिल्ली: गोवा के 'बर्चबाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए यह आदेश दिया। पीड़ित परिवारों के वकील ने बताया कि हिरासत बढ़ाने का उद्देश्य घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करना है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया और आग लगने के समय आपात प्रबंधन की स्थिति क्या थी।

बताया गया है कि २ दिसंबर को हुए हादसे के बाद लुथरा बंधु थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें क्लब



दिसंबर को भारत वापस लाया गया। इसके बाद से वे पुलिस हिरासत में हैं। इस मामले में क्लब के एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की थी, लेकिन जांच जारी रहेगी।

अंजुना पुलिस ने लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार

किया जा चुका है। इसके अलावा, ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो घटना के बाद यूनाइटेड किंगडम फरार हो गया था। उसके खिलाफ क्लब कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली: 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू, 4 दिनों में 10,000 वाहन फेल

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लागू किए गए 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम के तहत बीते चार दिनों में लगभग १०,००० वाहन अनिवार्य एमिशन टेस्ट में फेल हो गए हैं।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों और कार्यालयों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब बिना नोटिस के सीधे कार्रवाई की जाएगी, प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को सील किया जाएगा और वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का पालन न करने वाले ऑफिसों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सिरसा ने बताया कि दिसंबर तक नए PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) अवैध



फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं। मंत्री ने प्राइवेट कंपनियों को फीसदी स्टाफ क्षमता और वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी।

इसके अलावा, पूरे शहर में सड़कों की धुलाई और बायोमाइनिंग से कचरा निस्तारण

किया जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) और राजस्व विभाग के सहयोग से जल निकायों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लक्ष्य है कि पिछले कुछ वर्षों में गायब हुए कम से कम फीसदी जल निकायों को बहाल किया जाए।

दिल्ली में 120 किमी/घंटा स्फटार से दौड़ी AUDI, तीन कारों से टकरा कर ट्रक में घुसी

नई दिल्ली। ओखला फेज-एक में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। एक इलेक्ट्रिक ऑडी कार अनियंत्रित होकर सर्विस लेन के किनारे खड़ी तीन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी।

घटना में ऑडी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने से चालक सुरक्षित बच गया। उसे मामूली चोट आई, जिसे एक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने

बताया कि दोपहर पुलिस को ए, ओखला फेज-एक के सामने सर्विस रोड पर कई गाड़ियों की टक्कर को लेकर पीसीआर कॉल आई। टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ऑडी क्यू-आठ ई-ट्रान अनियंत्रित हो गई थी।

उसने पहले तीन खड़ी कारों को टक्कर मारी। फिर आगे एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में टकराने के बाद रुकी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में आडी कार चालक को हल्की चोट आयी है, जिसे एक्स ट्रामा

में भर्ती कराया गया है।

कार के भीतर या सर्विस रोड पर उस समय कोई नहीं था, ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और क्रैन के माध्यम से खींचकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना ले गई है। वहीं आडी कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटनास्थल पर मौजूद कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हमलोग अंदर बैठकर खाना खा रहे थे तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज आयी। जब

बाहर निकले तो देखा कि एक कार ने ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है, पर चालक अंदर से सुरक्षित निकला।

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अनुमान के अनुसार कार की रफ्तार कुछ किलोमीटर प्रतिघंटे से ऊपर रही होगी। सर्विस लेन पर इतनी तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने की जरूरत क्या थी। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा था अन्यथा यहां बड़ा हादसा हो सकता था।

नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर एक फायर टैंडर भेजे। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रविवार को रात नरेला इंडस्ट्रियल



एरिया में हरीश चंदर रोड के पास मौजूद एक फैक्ट्री से आग लगने की सूचना मिली। आग ने फैक्ट्री के

अंदर रखी मशीनरी, जूतों के डिब्बे और तैयार जूतों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया

कि बिल्डिंग यार्ड में फैली हुई थी, जिसमें एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी फ्लोर थे।

उन्होंने कहा, 'हमने एक फायर टैंडर मौके पर भेजे, और (सोमवार को) सुबह आग बुझा दी गई।' उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण: CAQM ने बैठक में लिए अहम फैसले

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को लेकर बैठक सोमवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के चेयरपर्सन राजेश वर्मा ने की। इसमें हवा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नवंबर को संशोधित ग्रेडेड रिसपॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को भी मंजूर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बदला गया है।

आयोग ने बताया कि प्रदूषण के अधिक स्तर पर लागू किए जाने वाले GRAP के नियमों में नीचे के सभी स्तरों के नियम अपने आप शामिल होंगे। मौजूदा सर्दियों के मौसम में GRAP के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई और बिजली आपूर्ति बनाए रखने, ट्रैफिक जाम कम करने, लोगों को जागरूक करने और सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने जैसे कदमों पर जोर दिया गया।

बैठक में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति को भी मंजूरी दी गई। इस समिति की अध्यक्षता IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला करेंगे। यह समिति वाहन प्रदूषण, स्वास्थ्य पर इसके असर, साफ-सुथरे परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी और नियमों में सुधार से जुड़े विषयों पर काम करेगी।

आयोग ने टैक्सी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए शून्य-उत्सर्जन वाहनों को अपनाने से जुड़े नियमों पर भी चर्चा की। तय किया गया कि मौजूदा क्लीट में BS-VI पेट्रोल दोपहिया वाहन दिसंबर तक शामिल किए जा सकेंगे, जबकि अन्य श्रेणियों में सामान्य पेट्रोल-डीजल वाहनों को व जनवरी खूब से शामिल करने पर

रोक रहेगी।

बैठक में के दौरान धान की पराली जलाने की स्थिति की समीक्षा की गई। आयोग ने बताया की तुलना में NCR में पराली जलाने की घटनाओं में करीब २० प्रतिशत की कमी आई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए कि वे में गेहूं की कटाई के समय पराली जलाने से रोकने के लिए राज्य स्तर पर कार्ययोजनाएं तैयार करें।

इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर की गई कार्रवाई, बंद और फिर से शुरू की गई फैक्ट्रियों तथा कानूनी मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे पर चिंता जताते हुए आयोग ने कहा कि इससे निकलने वाली धूल दिल्ली-एनसीआर में और प्रदूषण का बड़ा कारण है। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए कि वे धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराएं और निर्माण कचरे के सही निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बैठक में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर के आदेश के अनुसार BS-IV और उससे नए वाहनों को फिलहाल जबरन कार्रवाई से राहत मिलेगी, जबकि BS-III और उससे पुराने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। संबंधित एजेंसियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

आयोग ने कहा कि सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी विभागों को मिलकर लगातार निगरानी करनी होगी और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। सभी एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को पूरी गंभीरता से लागू करने की बात कही।

Muslims Must Step Forward With Individual and Collective Efforts for Communal Harmony in the Country: Syed Sadatullah Husaini, President, JIH

New Delhi: Jamaat-e-Islami Hind's Communal Harmony Department organised a two-day programme titled All India Communal Harmony Coordinators' Meet, in which men and women working at the grassroots level for communal harmony from nearly 20 states across the country participated. The objective of the meeting was to understand the situation of communal harmony in different states, review the work carried out so far, and provide guidance for future efforts. Addressing the gathering, the President of Jamaat-e-Islami Hind, Syed Sadatullah Husaini, said in his keynote address that work for communal harmony is not temporary but permanent in nature. He said Islam is founded on correcting relationships among people and guiding them in the right direction. He added that the Quran places great emphasis on this, and the Prophet

All-India Communal Harmony Coordinators' Meet Held in Delhi



Muhammad (pbuh) devoted his entire life to this cause. He further said there is now a need to take this work beyond the individual level and strengthen it at the institutional level so it rests on firm foundations. The Secretary General of Jamaat-e-Islami Hind, T Arif Ali, said efforts for communal harmony are not a response to

situational pressure. He said they are a responsibility and have always been part of the policy of Jamaat-e-Islami Hind. He added that just as harmony exists in every aspect of Allah's creation, harmony among human beings is also essential. On the occasion, Swami Sarvalok Anand Ji Maharaj spoke on the importance of inter-

faith dialogue for communal harmony and urged people to understand and respect their own beliefs as well as those of others. Gyani Mangal Singh Ji spoke on the importance of building bridges among all communities and said selfless service to people is the most effective means to achieve this. Ms Shaista Rifat, National Sec-

retary of Jamaat-e-Islami Hind, spoke on the role of women in communal harmony. She said half of the world's population cannot be kept away from this effort. She urged women to come forward and play an active role, and said society and the nation must provide them with maximum opportunities in this regard. During the programme, participants exchanged views on various ideas to make the Dharamik Jan Morcha and Sadbhavana Manch more active and effective across the country. Prof Salim Engineer, Vice President of Jamaat-e-Islami Hind, advised participants to work with confidence and without discrimination. At the conclusion of the programme, participants from across the country expressed their resolve to unite all sections of society with full strength, patience, wisdom, perseverance, and courage.

Railways hikes travel fares,AC tickets to cost Rs 10 more for every 500 km

New Delhi : Indian Railways will implement a rationalised passenger fare structure from December 26, 2025, under which fares for long-distance travel will increase

marginally while short-distance, suburban, and season ticket passengers remain unaffected. Under the revised structure, there will be no increase in fares for sub-

urban train services and monthly season tickets, Railways said. Ordinary Class passengers travelling up to 215 km will also not see any hike in ticket prices.

Despite No Stubble Burning or Firecrackers, Delhi Breathes Clean Air for Only 9 Days in Six Years

New Delhi: Even in the absence of stubble burning and firecrackers for much of the year, Delhi continues to remain a gas chamber. A startling data point underlines the severity of the crisis: over the past six years, residents of the national capital have experienced

clean air on only nine days. A thick blanket of smog has become a familiar sight for Delhiites stepping out of their homes. This persistent haze tells a grim story of air pollution, while debates and blame games dominate social media and television studios.

SUBSCRIPTION FORM


TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF

TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:
Language: English, Hindi and Urdu
Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W
No. of Pages: 12 pages (more in future)
Price: Rs. 3/-
Print order: 25,000
Periodicity: Weekly
Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.
Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page
Please Add Rs. 10 for outstation cheques.
50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc.
(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

अफ़गानिस्तान में अधिकारिक रूप से तिब्ब ए यूनानी की शुरुआत

डॉ. ओबैदुल्लाह बेग की मेहनत रंग लाई अफ़गानिस्तान और भारत सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में किया समझौता

नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर डॉ. ओबैदुल्लाह बेग की मेहनत रंग लाई है और अफ़गानिस्तान में तिब्ब ए यूनानी की अधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है। इस संबंध में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने दोनों देशों का शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुस्ताक अहमद और सेक्रेटरी जनरल डॉ. सैयद अहमद खान ने संयुक्त रूप से खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि भारत सरकार के इस कदम से तिब्ब ए यूनानी का और विकास होगा।

डॉ. ओबैदुल्लाह बेग ने कहा कि भारत सरकार, खासकर आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव के हम आभारी हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान



में तिब्ब ए यूनानी का एक नया चैप्टर शुरू किया है।

इस सिलसिले में जो डेलीगेशन अफ़गानिस्तान से मौलवी नूर जलाल

जलाली (पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर) की लीडरशिप में दिल्ली आया उसमें पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े अब्दुल्ला इसराइली, फजल रबी

करीमी, सैयद मुहम्मद इब्राहिम खेल, सैयद हारून आजाद, खालिद अहमद मुहम्मद अका, सैफतुल्लाह देवबंदी और मुजीब-उर-रहमान आफताब शामिल थे। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी की वजह से ही यह बड़ी कामयाबी मिली। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से अफ़गानिस्तान में यूनानी रिसर्च शुरू होगी और अफ़गान स्टूडेंट्स को भारत में फ्री बीयुएमएस (BUMS) की शिक्षा दी जाएगी।

जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉ. ओबैदुल्लाह बेग ने आगे कहा कि यह समझौता तिब्ब ए यूनानी को पसंद करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और इससे तिब्ब ए यूनानी और मजबूत होगी और इसे दुसरे देशों में भी बढ़ावा मिलेगा।

खोखली हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए खाएं अंजीर, दर्द और कमज़ोरी भागेगी दूर

नई दिल्ली। क्या आपकी हड्डियों में भी आए दिन दर्द रहता है और आपको चलने-फिरने में दिक्कत महसूस होती है। अगर हां तो फिर आपको आज से ही अपने खानपान में बदलाव कर लेना चाहिए।

अंजीर न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है जो सेहत और खासकर आपकी हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को पोषण प्रदान करता है और कई रोगों में राहत देने में कारगर है।

अंजीर में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और विटामिन-के हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। खासकर उन



लोगों के लिए जो पहले हड्डियों की कमजोरी से जूझ रहे हैं।

इसके अलावा अंजीर में कई एंटी-ऑक्सिडेंट्स और फाइबर भी होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखकर हड्डियों को स्वस्थ रखने में योगदान

देता है। अगर आप अंजीर को संतुलित डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आपको हड्डियों की मजबूती के साथ कई और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे।

अंजीर को आप कैसे भी खा सकते हैं। आप सूखे अंजीर इसे रोजाना स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर इन्हें ओटमील, दही या स्मूदी में मिलाकर भी खा सकते हैं। हड्डियों की हेल्थ के लिए आप इन्हें अगर दूध में भिगोकर खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि एक बात ध्यान रखें कि हड्डियों की मजबूती के लिए आपको विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए और साथ ही रोजाना कोई ना कोई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये सभी चीजें मिलाकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी और उन्हें बुढ़ापे तक मजबूत भी रखेंगी।

अंडे और फल ही नहीं, ये सस्ते फूड्स शरीर को अंदर से बनाते हैं मज़बूत, दूर भाग जाती हैं बीमारियां

नई दिल्ली। महंगे सप्लीमेंट्स से पहले थाली पर ध्यान देना भी जरूरी है। अदरक, पकी सब्जियां, ओटमील और उबला चावल जैसे रोजाना खाए जाने वाले फूड्स शरीर की हीलिंग पावर बढ़ाते हैं, सूजन कम करते हैं और इम्युनिटी मजबूत बनाते हैं।

आपका शरीर खुद को ठीक करने की जबरदस्त ताकत रखता है, बस जरूरत होती है उसे सही खाना देने की। लेकिन आज कल क्या देखा जा रहा है कि लोगों ने अपने शरीर की बागडोर खुद के बजाय दवाओं और सप्लीमेंट्स को दे दी है। जो हां, अक्सर लोग दवाओं और सप्लीमेंट्स पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि कुछ बेहद साधारण से फूड्स रोज खाने से ही शरीर की हीलिंग पावर मजबूत हो सकती है।

चौकिए मत। आपको अपने शरीर को अंदर तक से ठीक करने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की नहीं बल्कि सही तरह के खाने की जरूरत होती है। एन्सपर्ट्स के मुताबिक, अदरक, पकी हुई सब्जियां,

ओटमील जैसे कुछ फूड्स ना केवल आपकी इम्युनिटी को मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर की सूजन कम करने और पाचन सुधारने में भी मददगार हैं। खास बात ये है कि ये सभी चीजें हमारी रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा हैं। चलिए जानते हैं कैसे ये फूड्स आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को मजबूत करते हैं।

अदरक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक नेचुरल दवा की तरह काम करता है। इसमें मौजूद जिंजरॉल नाम का तत्व शरीर में सूजन को कम करता है और फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। रोजाना अदरक खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, उलटी, मतली और अपच में राहत मिलती है।

अदरक मसल्स और जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है, खासकर गठिया के मरीजों के लिए ये फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल

करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है। रोज प से ७ ग्राम अदरक चाय या खाने में डालकर लिया जा सकता है।

सब्जियां सेहत के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब इन्हें पकाकर खाया जाता है तो शरीर इन्हें और बेहतर तरीके से पचा पाता है। गाजर, पालक, ब्रोकली और टमाटर जैसी सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अवशोर्ब हो जाते हैं।

पकी हुई सब्जियों से विटामिन A, C, K, आयरन, पोटैशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। ये दिल को हेल्दी रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद करती हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। उबली या स्टीम की हुई सब्जियां पेट के लिए भी हल्की होती हैं। ओटमील एक ऐसा अनाज है, जो रोज खाने से शरीर को

कई फायदे मिलते हैं। इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन नाम का फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों का खतरा घटाता है। ओटमील धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

यही वजह है कि यह डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है। ओटमील पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन कम करने और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सेहत के लिए इस्टेंट ओट्स की बजाय रोलड या स्टील-कट ओट्स बेहतर माने जाते हैं।

उबला हुआ चावल शरीर को तुरंत और लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करता है। खासकर पारबॉइलड चावल में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो डाइजैस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है।

खेल समाचार

वैभव सूर्यवंशी के शौर्य पर काले बादल! जल्दी शोहरत, IPL में बरसता पैसा बन सकते हैं जंजाल



U-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की करारी हार ने यह साफ कर दिया कि प्रतिभा और रिकॉर्ड अपने आप बड़े मुकाबले नहीं जिताते। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक क्षमता के बावजूद, जल्दबाजी, दबाव और IPL में मिली जल्दी शोहरत उनके करियर के लिए चुनौती बन सकती है।

दुबई में खेला गया एसीसी मेन्स अंडर-19- एशिया कप 2025 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए आईना लेकर आया...और उस आईने में दिखी तस्वीर आरामदेह कतई नहीं थी।

पाकिस्तान के खिलाफ रनों की करारी हार ने बेरहमी से यह सच उजागर कर दिया कि प्रतिभा, रिकॉर्ड और गौरवशाली इतिहास बड़े मुकाबले नहीं जिताते, अगर तैयारी अधूरी और मानसिकता कच्ची हो।

यह पराजय किसी एक ओवर, एक कैच या एक गलत शॉट का नतीजा नहीं थी। यह रणनीति की विफलता, दबाव में टूटती बल्लेबाजी और बड़े मंच पर लिए गए गलत फैसलों का सामूहिक परिणाम थी।

... और इसी मलबे के बीच एक नाम ऐसा था, जिस पर उम्मीदों का सारा बोझ भी था, बहस की सारी आग भी और भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने का दबाव भी....वह नाम है- वैभव सूर्यवंशी।

भारत अंडर-19- एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम रही हैं शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत ने रिकॉर्ड ८ बार खिताब जीता है। इस दौरान टीम 2025 में पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता भी रही। ऐसे गौरवशाली इतिहास के साथ फाइनल खेलना सिर्फ समान नहीं, बल्कि दबाव भी लाता है। दुबई में भारतीय टीम उस दबाव से निपट नहीं सकी।

वैभव सूर्यवंशी इस टीम का चेहरा थे। यूएई के खिलाफ वक्त्र रनों की विस्फोटक पारी ने उन्हें टूर्नामेंट का पोस्टर बॉय बना दिया। उस पारी में उनकी नैसर्गिक प्लेयर, विस्फोटक ताकत और आत्मविश्वास साफ झलकता था।

...लेकिन उसी पारी ने उनके खेल को एक तथ्य फ्रेम में भी कैद कर दिया- हाई-इंटेंटे, हर गेंद पर हमला। इसके बाद पूरे टूर्नामेंट में वह सिर्फ एक बार के आंकड़े तक पहुंचे, वह भी मलेशिया जैसे कमजोर विपक्ष के खिलाफ। फाइनल में पाकिस्तान के सामने टॉप ऑर्डर पर उनका जल्दी आउट होना भारत की हार के अहम कारणों में से एक रहा।

फाइनल ने यह भी दिखा दिया कि पेशेवर क्रिकेट सिर्फ ताकत और आक्रामकता का खेल नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, स्ट्राइक रोटेशन करना और सही समय पर फैसले लेना उतना ही जरूरी है। पाकिस्तान ने वैभव के खिलाफ यही किया- क्वालिटी स्पिन, हार्ड लेंथ और सिंगल्स पर सख्त नियंत्रण। वैभव उस जाल को पढ़ नहीं सके।

फाइनल में पाकिस्तान के अली रजा के साथ हुआ गर्मागर्म वाकया और विरोधी खिलाड़ी की ओर किया गया 'जूते वाला इशारा' व्यापक रूप से भावनात्मक अपरिपक्वता के संकेत के तौर पर देखा गया। कच्ची प्रतिभा मैच जीत सकती है, लेकिन टेम्परामेंट ही चैम्पियन बनाता है।

वैभव ने बेहद कम उम्र में राजस्थान रॉयल्स जैसी IPL टीम जॉइन की। इतनी जल्दी पैसा, शोहरत और पहचान मिलना आकर्षक है, लेकिन खतरनाक भी। इतिहास ऐसे खिलाड़ियों से भरा है जो पहली बड़ी रकम के बाद दिशा खो बैठे।

वैभव को अपने सीनियर साथी यशस्वी जायसवाल जैसे उदाहरण से सीख लेनी चाहिए। जायसवाल ने तेज सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहकर अनुशासन और फोकस बनाए रखा। IPL उनके लिए मंच है, मंजिल नहीं।

वैभव सूर्यवंशी कच्चा हीरा हैं, लेकिन हर हीरे को तराशने की जरूरत होती है। इस सफर में जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है- कोच और मेंटर्स की भी बड़ी भूमिका है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी सीखने की प्रक्रिया में पैर नहीं खिसकाएं, अनुभवों से सीखें और बड़े मंच पर संतुलन बनाएं।

अगर वैभव यह सब हासिल कर लेते हैं, तो उनकी प्रतिभा सिर्फ चमक नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्थायी प्रभाव छोड़ने वाली ताकत बन जाएगी।

ذہنی دھند: دماغ کی بغاوت یا جدید زندگی کی المیاتی پیداوار؟

اسما، جبین فلک

علی کو وہ لمحہ اپنی روح پر ایک نقش کی طرح یاد ہے۔ وہ اپنے کیریئر کی بلند ترین عمارت کے کانفرنس روم میں تھا، جہاں ہر نظر ایک عدسے کی طرح اس پر مرکوز تھی۔ اچانک، اس کے ذہن میں کچھ ٹوٹ گیا۔ جیسے کسی نے شعور کی ہارڈ ڈرائیو پر فارمیٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ وہ الفاظ جو اس کی زبان پر تھے، بھاپ بن کر اڑ گئے۔ وہ اعداد و شمار جن پر اس کی کامیابی کا انحصار تھا، ایک بے معنی گورکھ دھندے میں تبدیل ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے خیالات کا بہاؤ مجمد ہو گیا ہے اور وہ ایک خالی، گونجتی ہوئی خاموشی میں قید ہے۔ کمرے کی روشنیاں ناقابل برداشت حد تک تیز محسوس ہونے لگیں اور کانوں میں ایک ہلکی سی سنسنائٹ نے ہر دوسری آواز کو دبا دیا۔ یہ محض یادداشت کی ناکامی نہیں تھی، یہ اس کے وجود کا اپنے ہی دماغ سے رابطہ منقطع ہو جانے کا ایک دہشت ناک تجربہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علی نے پہلی بار "برین فاگ" کو ایک طبی اصطلاح کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی ذات کے انہدام کی ایک زندہ حقیقت کے طور پر محسوس کیا۔ علی کی یہ کہانی محض ایک فرد کی داستان نہیں، بلکہ یہ جدید دور کے انسان کا اجتماعی المیہ ہے۔ ہم ایک ایسی تہذیب میں جی رہے ہیں جو رفتار، پیداوار اور ہر لمحہ "آن لائن" رہنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ اس تناظر میں، ذہنی دھند یا برین فاگ (Brain Fog) کوئی خرابی یا بیماری نہیں، بلکہ یہ ہمارے حیاتیاتی وجود کی طرف سے ایک بغاوت ہے۔ یہ ہمارے جسم اور دماغ کا اس غیر فطری رفتار کے خلاف ایک انتہائی نظام ہے، ایک تنبیہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی فطری حدود سے بہت تجاوز کر چکے ہیں۔ اس ذہنی بغاوت کی جڑیں ہمارے سونے کے کمروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کارپوریٹ کلچر اور مسابقت کی دوڑ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیند ایک عیاشی ہے، جسے کم کر کے پیداوار تیز بڑھائی جاسکتی ہے۔ علی کی کہانی اس کی ایک تلخ مثال ہے، جو اکثر رات گئے تک ای میلز اور پریزنٹیشنز میں الجھا رہتا، اور بچا کچھا وقت اسکرین پر گزار دیتا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ نیند دماغ کے لیے محض آرام نہیں، بلکہ ایک فعال صفائی کا عمل ہے۔ معروف نیوروسائنسٹ



مایکن نیڈرگارڈ (Maiken Nedergaard) نے 2012 میں "گلیمفیک سسٹم" (Glymphatic System) کو دریافت کر کے یہ ثابت کیا کہ گہری نیند کے دوران دماغی اسپائل فلویڈ ہمارے دماغ کو دھو کر ان زہریلے پروٹینز (مثلاً بٹا امیلو ایڈ) کو صاف کرتا ہے جو دن بھر کے ذہنی کاموں کے نتیجے میں جمع ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو یہ کچرا ہمارے نیورازز کے درمیان جمع ہوتا رہتا ہے، جو اگلے دن سوچنے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، توجہ کو منتشر کرتا ہے اور یادداشت کو کمزور بناتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شہر کا صفائی کا نظام رات کو کام کرنا چھوڑ دے اور اگلے صبح ہر گلی کوڑے کے ڈھیر سے بھری ہو۔ اگر نیند کی کمی اس مسئلہ کا ایک پہلو ہے تو ڈیجیٹل دور کا معلومات کا سیلاب اس کا دوسرا، اور شاید زیادہ خطرناک، پہلو ہے۔ ہم ایک "توجہ کی معیشت" (Attention Economy) میں جی رہے ہیں، جہاں ہماری توجہ ایک قیمتی شے ہے جسے ہر قیمت پر خریدا اور بیجا جاتا ہے۔ اسٹیفو رڈ یونیورسٹی کے نیوروسائنسٹ ڈاکٹر

اینڈریو ہوبرمین (Andrew Huberman) وضاحت کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا، ٹوٹیکلینز اور لائٹناہی اسکروولنگ ہمارے دماغ کے ڈوپامین سسٹم کو بائی جیک کر لیتے ہیں۔ ہر لائیک، کمینٹ یا نئی پوسٹ ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتی ہے، جو ہمیں بار بار اپنے فون کی طرف کھینچتا ہے۔ اس مسلسل خلفشار کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ طویل مدتی، گہری توجہ کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی، فوری تسکین کا عادی ہو جاتا ہے۔ علی کو یہ احساس نہیں تھا کہ رات کو بستر پر لیٹ کر "صرف پانچ منٹ" کے لیے فون دیکھنا دراصل اس کے دماغ کو اگلے دن کی ناکامی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ صرف نیلی روشنی کا مسئلہ نہیں، یہ دماغ کو ایک مستقل اضطراب اور بے چینی کی حالت میں مبتلا رکھنے کا عمل ہے جو ذہنی وضاحت کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے یا ذہنی انحطاط، کہ تاریخ کی سب سے زیادہ معلومات تک رسائی رکھنے والی نسل اپنی توجہ کو چند سیکنڈز سے زیادہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کھو رہی ہے؟ یہ ذہنی دھند صرف ہمارے سروں میں ہی نہیں، بلکہ ہمارے پورے وجود میں جڑیں رھتی ہے، جس کا

نعمت ثابت ہوئی۔ اس نے اسے رکے اور سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے پہلی بار اپنے جسم کے پیچھے گئے انتہائی گھٹن کو سنجیدگی سے لیا۔ اس کا حل کسی جادوئی گولی میں نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلنے میں تھا۔ اس نے صبح کرفون چیک کرنے کی بجائے دس منٹ صرف اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کرنا شروع کی۔ اس نے ملٹی ٹاسکنگ کو خیر باد کہا اور ایک وقت میں ایک کام کرنے کے قدیم اصول کو دوبارہ اپنایا۔ اس نے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹیکنالوجی سے ناٹوڑ کر کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اس نے اپنی میز سے انرجی ڈرنکس ہٹا کر پانی کی بوتل اور پھل رکھ لیے۔ یہ تبدیلیاں معمولی تھیں، لیکن ان کے اثرات گہرے تھے۔ مہینوں کی مسلسل کوشش کے بعد، اس نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن کا اندرونی موسم بدل رہا ہے۔ دھند چھٹ رہی تھی، اور سوچ کا نیلا آسمان دوبارہ نظر آنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ذہنی وضاحت کوئی ایسی چیز نہیں جسے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہماری فطری حالت ہے جسے ہم نے جدید زندگی کے شور میں کھو دیا ہے۔ آخر میں، برین فاگ کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ ہم سے ایک بنیادی سوال پوچھتا ہے: ہم اپنی دنیا تعمیر کر رہے ہیں؟ ایک ایسی دنیا جو انسانی ذہن کی حیاتیاتی حقیقت کا احترام کرتی ہے، یا ایک ایسی دنیا جو اسے ایک مشین سمجھ کر اس کی آخری حد تک تجوڑ لینا چاہتی ہے؟ اس دھند سے نکلنے کا راستہ مزید تیز رفتار انہیں یا باپو ہینکس ٹیٹش میں نہیں، بلکہ سست ہونے، قدرت سے جڑنے، حقیقی انسانی تعلقات استوار کرنے اور اپنے جسم کی دانائی کو سننے میں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنے آقا کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے انسانی مقاصد کے حصول کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کریں۔ علی کی طرح، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، بلکہ آج ہی سے ان خاموش گھنٹوں پر توجہ دینی ہوگی جو ہمیں ایک زیادہ متوازن اور حقیقی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ شاید تب ہی ہم ہمیشہ کے مجموعی اس ذہنی دھند سے نکل کر ایک روشن اور واضح مستقبل کی طرف دیکھ پائیں گے۔

نفرت اور محبت

وجہ سے انہیں اسرائیل کی تاریخ کا بدترین وزیراعظم قرار دیتے ہوئی جس کی وجہ سے اسرائیل کی شاندار عسکری کامیابی نے کوئلہ دیں۔



پچھلے دنوں گولڈا مئیر کے پوتے نے اسرائیل کی نیوز

مئیر کو سیاسی طور پر مضبوط نہیں بلکہ کمزور بنایا بہت سے اسرائیلی اسی

غزالہ عزیز

لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امریکا اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کب قائم ہوا وہ بھی اتنا گہرا کہ امریکا اپنا منیج، اپنا فائدہ دونوں کی پروا نہ کرے دنیا میں اٹھتے نفرت کے طوفان کو نظر انداز کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے اسرائیل کی غرہ میں دردنگی، قتل و غارت گری اور نسل کشی میں امریکا کی پشت پناہی دنیا کو نظر نہیں آ رہی؟ سب جانتے ہیں بس بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نفرت جو اسرائیل کے لیے ہے وہ امریکا کے لیے بھی موجود ہے اظہار کرتے خوف کھاتے ہیں۔

امریکا اسرائیل اتحاد کی کم از کم پچاس سالہ طویل تاریخ ہے اور یہ اتحاد قائم کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ اسرائیل کی سابق وزیراعظم گولڈا مئیر کا تھا اگرچہ وہ اس وقت وزیر خارجہ تھی لیکن انہوں نے اس بات کے لیے اقوام متحدہ کو تیار کیا کہ اسرائیل کی آواز کو سنا جائے اور مانا جائے انہوں نے امریکا کو اس وقت یعنی 1956ء میں اسرائیل کو تھکایا فروخت کرنے پر بھی راضی کیا اگرچہ ان کے درمیان اس وقت اتنی قربت نہیں تھی لیکن گولڈا مئیر ایک ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے اسرائیل کو 1967ء میں چھ دن کی جنگ میں اسرائیلی کو شاندار عسکری کامیابی دلائی لیکن چونکہ جنگ میں اسرائیل کے 2700 فوجی ہلاک ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو گولڈن مئیر کی ناکامی کے طور پر دیکھا گیا۔ انہوں نے جنگ کے بعد وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وجہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی سپاہیوں کی ہلاکت تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بخیرہ نہیں لیا کہ مصر اور شام حملہ کریں گے، حالانکہ انہیں اردن کے بادشاہ کی جانب سے مطلع کیا جا چکا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی انٹلیجنس ایجنٹوں کی بات پر اعتبار تھا جنہوں نے اس کو بخیرہ خطرہ قرار نہیں دیا تھا مگر جب شام اور مصر نے ایک ساتھ اسرائیل پہ

ایجنسی کو بتایا کہ جنگ کے بعد سابق وزیراعظم کے لیے خاص طور پر ان کے حامیوں کی طرف سے گولڈا مئیر کے ساتھ نفرت اور ان کے حامیوں کے ساتھ نفرت میں عورت سے نفرت ایک سخت نا انصافی تھی یعنی ان کا عورت ہونا اگرچہ انہوں نے ریاست کے لیے انتہائی بنیادی اور اہم کردار ادا کیا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کے قیام کے دوسرے پہلو پر غور کرنے میں ناکام اور نا اہل تھیں اور اسی لیے فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ دوسرا پہلو فلسطینیوں کی وہاں موجودگی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست میں ایک آزاد فلسطینی عوام کب تھے ایسا نہیں تھا کہ فلسطین میں کوئی فلسطین تھا جو اپنے آپ کو فلسطینی قوم سمجھتا تھا اور ہم نے انہیں باہر نکال دیا اور ان کا ملک چھین لیا، وہ یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی یہ بات اور اسرائیل کی تحقیق اس بات کی علامت ہے کہ فلسطینیوں کی شناخت کو نظر انداز کیا گیا، مسلم امہ خاص طور سے عرب خاموش رہے بلکہ اسرائیل کو مدد دی جو آج بھی اسی طرح ہے لیکن آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے یکجا بھی ہے آج سوشل میڈیا عوام کو سچ بتانے اور سمجھانے کے لیے بہت اہم ہے۔ گولڈا مئیر کے یہ جملے اگر آج بولے گئے ہوتے تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا دینے میں کامیاب ہو جاتے آج سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے اور نہ کیا جاسکتا ہے۔ لوگوں کا روایتی میڈیا کی نسبت سوشل میڈیا پر اعتبار بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے دسترس میں ہے۔ یہاں وہ کسی سے کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں، ثبوت مانگ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بات کرنے والا کتنا معتبر اور اس کی بات میں کس قدر وزن ہے لہذا دنیا بھر کے اور پاکستان کے عوام کے لیے سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب ایک نئی طاقت اور ایک نیا ہتھیار ہے۔

Jamiat Applauds Karnataka's Anti-Hate Speech Law

The Nation Must Unite in a Collective Fight Against Hate: Maulana Mahmood Madani

New Delhi : The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani, has welcomed the passage of a law by the Karnataka Assembly aimed at preventing hate speech and hate-based crimes.

He said that the Supreme Court of India has repeatedly observed that a "climate of hate prevails in the country," which poses a serious threat to social harmony, fraternity, and the democratic fabric of the nation.

Against this backdrop, the initiative taken by the Karnataka government is a positive and significant step towards promoting social cohesion and upholding the constitutional values enshrined in the Constitution of India.

Maulana Madani stated that Jamiat Ulama-i-Hind has consistently and for a long time been demanding the enactment of an



effective and comprehensive law to curb hate and hate-driven violence.

In this regard, the Jamiat has undertaken several initiatives both within and outside the courts, and has also established a dedicated department to address and counter the growing menace of hate. He recalled that it was on the petition filed

by Jamiat Ulama-i-Hind that the Supreme Court of India directed all states to ensure strict and effective implementation of the Tehseen Poonawalla Guidelines.

Referring to the April 2023 observations of the Supreme Court, Maulana Madani said that the Apex Court had categorically held that taking action

against hate speech is a constitutional responsibility of the state machinery. The Court further emphasized that authorities should not wait for formal complaints, but must act suo motu to prevent and curb such offences.

However, he expressed regret that despite these clear directions, most states have so far failed to

take concrete and effective steps. In this context, the proactive initiative taken by the Karnataka government offers a much-needed ray of hope.

Maulana Madani stressed that the success of any law against hate and violence does not depend merely on its enactment, but rather on its fair, transparent, and

non-discriminatory implementation.

He underlined the need for a careful and comprehensive study of the law, and for removing any ambiguities in its definitions, so that no future government is able to misuse it as a tool against minorities or other vulnerable sections of society.

Reiterating his resolve, Maulana Mahmood Madani said that Jamiat Ulama-i-Hind will continue its principled struggle across the country for peace, fraternity, and the supremacy of the Constitution.

Maulana also appealed to all state governments to enact effective laws against hate speech and hate-based crimes in the light of the directions issued by the Supreme Court, so that those who spread hatred and poison social harmony can be held accountable.

Karnataka Assembly Passes Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill Amid BJP Opposition

Bengaluru:

The Karnataka Legislative Assembly on Thursday passed the Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill, 2025, amid strong opposition and repeated disruptions by the Bharatiya Janata Party (BJP). The Bill proposes stringent penalties, including imprisonment of up to seven years and a fine ranging from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh, for individuals or organisations found guilty of promoting hatred.

Introducing the Bill, Home Minister G. Parameshwara said the legislation was necessary to curb the growing instances of hate speech and hate crimes in society. He noted that inflammatory statements made through speeches, books or electronic media could



have serious social consequences if left unchecked.

Participating in the debate, the Home Minister became emotional while sharing his personal experiences of discrimination during childhood. He emphasised that hatred based on religion, caste and gender was on the rise and needed to be addressed firmly through law. Stressing the importance of

constitutional values, he said true equality could be achieved only by fully implementing the Constitution drafted under the leadership of Dr B.R. Ambedkar.

According to the government, the law will apply not only to fresh content but also to previously published material that promotes hatred. The objective, Parameshwara said,

is to prevent the spread of divisive narratives and ensure social harmony.

Opposition Leader R. Ashoka strongly opposed the Bill, calling it an attack on freedom of expression. Questioning the need for such legislation 75 years after Independence, he alleged that the law could be misused to target political opponents and suppress dissent. He also claimed

that the Bill lacked adequate safeguards, including clear provisions for bail, and warned that journalists could be jailed under its provisions.

Ashoka described the Bill as a "political weapon" and cautioned the ruling party that it could be used against them in the future as well. He urged the government to exercise caution before enacting such a law. The debate witnessed heated scenes after Minister Byrathi Suresh made remarks concerning people from the coastal region, triggering protests from BJP legislators. The House saw repeated interruptions, with BJP MLA Sunil Kumar raising objections and pointing towards the Speaker. Despite the uproar, the government succeeded in passing the Bill.

حکومت نے منریگا پر چلایا بلڈ وزر، غریبوں کے روزگار پر حملہ: سونیا گاندھی



انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ دہلی میں بیٹھ کر کیا جائے گا کہ کس کو، کہاں، کتنا اور کس طرح روزگار ملے گا، جو زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے بقول منریگا کو لانے اور نافذ کرنے میں کانگریس کا کردار ضرور تھا مگر یہ کبھی پارٹی مفاد کی اسکیم نہیں رہی، بلکہ ملک اور عوام کے مفاد سے جڑی ایک جامع پالیسی تھی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ اس قانون کو کروڑوں کسانوں، مزدوروں اور دیہی غریبوں کے مفادات پر ضرب لگائی ہے۔

قانون غریب طبقے کے لیے سہارا ثابت ہوا۔ سونیا گاندھی کے مطابق افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حال ہی میں نہ صرف منریگا سے

نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی (سی پی پی) کی چیئر پرسن سونیا گاندھی نے منریگا (مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی قانون) میں ترمیم پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے اس فلاحی قانون پر بلڈ وزر چلا دیا ہے۔ دہلی سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ منریگا محض ایک سرکاری اسکیم نہیں بلکہ دیہی ہندوستان کے غریب، محروم اور بے زمین طبقات کے لیے روزگار کے قانونی حق کی ضمانت تھا، جسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ سونیا گاندھی نے یاد دلایا کہ تقریباً 20 برس قبل ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت میں پارلیمنٹ نے منریگا قانون کو اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک انقلابی قدم تھا جس سے کروڑوں دیہی خاندانوں کو فائدہ پہنچا، پتل مکانی میں کی آئی، گرام پنچایاتوں کو طاقت ملی اور مہاتما گاندھی کے گرام سواراج کے تصور کو عملی شکل دینے کی سمت مضبوط پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں موجودہ حکومت نے منریگا کو کمزور کرنے کی مسلسل کوششیں کیں، حالانکہ کووڈ کے مشکل دور میں یہی

احمد آباد میں خاتون کو تھپڑ مارنے پر پولیس اہلکار معطل

احمد آباد: گجرات میں ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر پولیس اہلکار معطل ٹریفک کی خلاف ورزی پر خاتون کے ساتھ بھگڑے کے بعد مدینہ طور پر تھپڑ مارنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے، حکام نے ہفتہ کو بتایا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ٹریفک ویسٹ) بھادوانی ٹیل نے صحافیوں کو بتایا، ملزم ہیڈ کانسٹیبل جینتی بھائی جالا کو معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے مدینہ طور پر ایک خاتون کو ان کا شناختی کارڈ کراہنے پر تھپڑ مارا تھا۔ حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ یعنی 19 دسمبر کو پیش آیا جب ایک خاتون مدینہ طور پر پالڈی علاقے میں بغیر ہیلمٹ کے دو پہیہ گاڑی پر سوار تھی۔ جالانے خاتون کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روک دیا۔ صورتحال اس وقت بڑھ گئی جب خاتون نے مدینہ طور پر کانسٹیبل کا شناختی کارڈ دیکھنے کا مطالبہ کیا اور بدتمیزی کی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ٹیل نے کہا، جب کانسٹیبل نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تو خاتون نے مدینہ طور پر اسے زمین پر گرادیا۔ اس کے بعد کانسٹیبل مشتعل ہو گیا اور اسے تھپڑ مار دیا۔

’ووٹ چوری کر مودی حکومت نے لوگوں سے صاف ہوا پانی کا حق چھین لیا، دہلی میں بڑھتی آلودگی پر کانگریس کا تلخ تبصرہ



47 شہر ہندوستان کے ہیں۔ دہلی۔ این سی آر کے کم و بیش سبھی علاقوں کا اے کیو آئی 400 پار ہے۔ یہ سب سے خطرناک ’ہزار ڈس‘ (زہریلا) زمرہ میں آتا ہے۔“ اس ویڈیو کے ساتھ کانگریس نے کنیشن دیا ہے ’صاف ہوا کا وعدہ بھی جملہ نکلا‘ قابل ذکر ہے کہ مودی حکومت فضائی آلودگی سے ہونے والی اموات معاملہ پر لگا تار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس تعلق سے نہ ہی وزیر اعظم نریندر مودی کچھ بول رہے ہیں، نہ ہی ان کے وزراء حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کچھ بی بی سی لیڈران سوال پوچھ جانے پر ٹال مٹول والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا پھر اپوزیشن کے سوالات کو ٹھنڈے ’سیاسی‘ قرار دے دیتے ہیں۔ جب مودی حکومت سے سوال کیا جاتا ہے، جو جواب ملتا ہے کہ خصوصی طور پر فضائی آلودگی سے ہونے والی اموات کا براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی حتمی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔

پیشتر کی ہے، جس میں پی ایم مودی کی ایک پرانی تقریر موجود ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں ’منتخب 100 شہروں میں آلودگی کم کرنے کے لیے ہم ایک پاک نظریہ کے ساتھ ایک مشن موڈ میں کام کرنے والے ہیں۔“ ویڈیو میں جیسے ہی پی ایم مودی کی تقریر ختم ہوتی ہے، ہندوستان میں آلودگی کے موجودہ حالات سے متعلق ایک خبر پیش کی جاتی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ”ہم نے دنیا بھر کے سب سے آلودہ 50 شہروں کی لائسنس چیک کی۔ ان 50 میں

نئی دہلی: دہلی میں فضائی آلودگی اپنے عروج پر ہے۔ ساتھ ہی دہلی میں زیر زمین پانی بھی زہریلا ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ٹی رپورٹس سامنے آچکی ہیں، لیکن مرکزی مودی حکومت ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور نہ ہی دہلی کی بی بی سی حکومت نے کوئی مثبت پیش رفت کی ہے۔ کانگریس نے اس تعلق سے بی بی سی اور وزیر اعظم مودی کو لگا تار نشانہ بنارہی ہے۔ آج اپنے ’ایکس‘ ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت ’ووٹ چوری‘ کر لگا تار عوام سے ان کے حقوق چھین رہی ہے۔ ویڈیو میں دہلی کی فضائی اور آبی آلودگی سے متعلق کچھ تصویریں پیش کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ آواز کے ساتھ مودی حکومت پر حملہ آور انداز میں بتایا گیا ہے کہ ”آرٹی آئی ختم کیا، منریگا ختم کیا، اب یہ حقوق جنگلات قانون ختم کریں گے۔ اس کے بعد حصول ارضی قانون کو مٹائیں گے۔“ ویڈیو میں یہ بھی کہا

دہلی میں آلودگی اور کھرے کے ساتھ سردی کا قہر!

نئی دہلی: دہلی۔ این سی آر میں گھرے کھرے ساتھ ساتھ سردی نے بھی لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہری شدید سردی کی زد میں ہیں اس دوران ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے بھی پورے این سی آر کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہفتہ کو موسم کی اچانک تبدیلی کے باعث دن اور رات شدید سردی محسوس کی گئی۔ راجدھانی دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیوس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیوس ریکارڈ کیا گیا جب کہ غازی آباد کا اے کیو آئی 441 تک پہنچ گیا جو صورتحال کی سنگین کو ظاہر کرتا ہے۔ دہلی۔ این سی آر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اچانک موسم بدل گیا ہے اور صبح سے ہی گہرا کھرا چھا ہوا ہے۔ دن بھر ٹھنڈی ہواؤں نے لوگوں کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔

پنجاب میں لڑکی کا سر عام گولی مار کر قتل، علاقے میں سنسنی



گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ نہر کے آس پاس اور اطراف کے مواصلات میں جھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی ترن تارن نے یقین دلایا کہ ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور کیس کی گہرائی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کر کے علاقے میں سیکیورٹی بڑھادی گئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ سطح پر معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ حملہ آوروں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جاسکے۔

لگانے کے لیے قریبی علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اے بی بی نیوز کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی، معاشقہ یا پرانے تنازع سے جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ تمام امکانات کی سنجیدگی سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ متاثرہ کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس کی موت کی خبر پھیلنے ہی اہل خانہ اور رشتہ داروں میں کھرام مچ گیا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ لوگوں نے پولیس سے جلد ملزمین کو

ترن تارن: پنجاب کے ضلع ترن تارن میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ رسول پور نہر کے قریب سڑک کنارے کھڑی ایک لڑکی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے تازہ توڑ فائرنگ کر دی جس سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ دن دھاڑے پیش آنے والی اس واردات سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک موٹر سائیکلوں پر سوار دو تین نوجوان وہاں پہنچے۔ انہوں ایک لفظ کہے بغیر لڑکی پر فائرنگ کر دی اور تیزی سے فرار ہو گئے۔ گولی لگتے ہی متاثرہ زمین پر گر گئی۔ راکبہروں نے اسے فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا لیکن وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ترن تارن پولیس کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ جائے وقوعہ سے گولیوں کے خول اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ حملہ آوروں کی شناخت اور ان کے موٹر سائیکل نمبر کا پتہ

اکھلیش یادو نے کہا ارواوی بچے کی تو دہلی بچے کی! غیر ملکی چھوڑیے، ملکی سیاح بھی نہیں آئیں گے



خبردار کیا کہ اگر ارواوی کی تباہی نہیں روکی گئی تو دہلی کے شہریوں کو ہر سانس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی کا سب سے خطرناک اثر بزرگوں، بیماروں اور بچوں پر پڑ رہا ہے۔ ان کے مطابق آلودگی سے دہلی کے میڈیکل اور اسپتال کا شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے اور جو لوگ علاج کے لیے آتے تھے اب وہ آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اکھلیش یادو نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی تو دہلی شمالی ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی مرکز کے طور پر بھی اپنی اہمیت کھودے گا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ غیر ملکی سیاح آئیں گے اور نہ ہی ملک کے اندر سے سیاح دہلی کا رخ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑے سیاسی، تعلیمی، علمی، سماجی اور ثقافتی پروگرام بھی بند ہو سکتے ہیں۔ الپکس، کامن ویلتھ گیمز یا ایشین گیمز جیسے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ وہیں ارواوی کی نئی تعریف کے خلاف زمینی سطح پر بھی احتجاج تیز ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے قدیم ترین پہاڑی سلسلے کے ماحولیاتی توازن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

کہ ارواوی کو بچانا کوئی متبادل نہیں بلکہ لازمی عزم ہے۔ ان کے مطابق ارواوی بچنے رہے گی تبھی دہلی اور این سی آر محفوظ رہ پائیں گے۔ انہوں نے ارواوی کو قدرتی حفاظتی ڈھال قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی پہاڑی سلسلہ فضائی آلودگی کو کم کرنے، بارش کے پانی انتظام اور درجہ حرارت کے توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ ارواوی این سی آر کی حیاتیاتی تنوع میں بڑھتی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جو گیلے علاقوں، پرندوں اور ماحولیاتی توازن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جذباتی پہلو پر زور دیتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ ارواوی دہلی کے ثقافتی اور تاریخی ورثے کا حصہ ہے۔ انہوں نے

نئی دہلی: ملک کے قدیم ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ارواوی کی اونچائی پر بنی نئی تعریف پراسی اور سماجی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں کے احتجاج کے درمیان اپوزیشن نے بھی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سماجی پارٹی (ایس پی) کے صدر اکھلیش یادو نے اسے دہلی اور این سی آر کے مستقبل سے متعلق سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ارواوی تنازعہ براہ راست ماحولیات، آلودگی پر قابو پانے اور عوامی زندگی سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ ایس بی صدر اکھلیش یادو نے ارواوی پہاڑیوں کے بارے میں ایک لمبی پوسٹ شیئر کی ہے۔ جس میں انہوں نے لکھا

SAMLA Observes Minority Rights Day, Calls for Justice, Equality and Constitutional Morality



New Delhi: The South Asian Minorities Lawyers Association (SAMLA) marked Minority Rights Day at the India Islamic Cultural Centre, bringing together senior jurists, former judges, leading advocates, academics and human rights defenders. The programme, themed “Minorities’ Rights – South Asian Perspective”, focused on the growing challenges faced by minorities across the region. Over 40 senior lawyers were felicitated for completing 35 years of distinguished service to the legal profession.

Salman Khurshid, Senior Advocate and former External Affairs Minister, reaffirmed his

commitment to SAMLA’s mission, stressing that coexistence rooted in morality, culture and shared humanity is the only ethical and sustainable response to social divisions. Drawing from John Rawls’ The Idea of Justice, he underlined fairness, constitutional values and informed democratic participation.

Justice Iqbal Ansari, former Chief Justice of the Patna High Court, described equality as a timeless struggle and asserted that democracy survives on the principle of “agreeing to disagree.” He cautioned against the political misuse of religion and emphasised that the Constitution remains India’s strongest safe-

guard of freedom.

Senior Advocate of Supreme Court Chander Uday Singh warned against the growing “normalisation of persecution,” recalling past communal targeting and condemning hate crimes, mob lynchings and the misuse of laws that criminalise interfaith relationships. He urged citizens to resist injustice by saying, “not in my name.”

Sr. Advocate Nasir Aziz, President of SAMLA, pledged renewed resolve to defend minority rights across South Asia. Sr. Advocate Rakesh Khanna, former President of the Supreme Court Bar Association, highlighted con-

stitutional safeguards for minorities, while Mr. Wajahat Habibullah, former Chairman of the National Commission for Minorities, stressed the proactive role of minorities in nation-building.

During the programme, SAMLA adopted a comprehensive resolution reaffirming its commitment to protecting the religious, ethnic, linguistic and cultural rights of minorities in South Asia. A souvenir of SAMLA was released on the occasion. The welcome address was delivered by Feroz Khan Ghazi, who highlighted SAMLA’s contributions and the continuing challenges faced by minorities.

Service as a Commitment

Central Bank of India Sets a Strong Example of Social Responsibility



New Delhi : On the auspicious occasion of its 115th Foundation Day, Central Bank of India’s Delhi South Regional Office organised a special social service programme at Katyayani Balika Ashram, Jhandewalan, New Delhi, dedicated to the holistic welfare of tribal girls. The initiative reflected the Bank’s continued commitment to social responsibility and inclusive development.

As part of the programme, essential items aimed at supporting

the girls’ daily lives and education were distributed, including a washing machine, school bags, personal utility materials and other useful supplies. The initiative was designed to strengthen educational access and improve living conditions for the residents of the ashram.

The programme was held in the gracious presence of Shri Anil Agnihotri, Regional Head, and Shri Mandeep Kumar, Deputy Regional Head. Senior bank of-

icials and staff members, including Shri Tarun Sharma, Ms Sarika and Ms Anubha, were also present and actively participated, adding meaningful value to the occasion.

Addressing the gathering, Shri Anil Agnihotri encouraged the girls to pursue education, self-reliance and a brighter future, while reaffirming Central Bank of India’s steadfast commitment to the empowerment of all sections of society. He highlighted the importance of collective responsibil-

ity in building an inclusive and equitable future.

This initiative stands as a strong example of the Bank’s dedication to corporate social responsibility, community welfare and inclusive growth. Marking 115 years of distinguished service, the programme vividly embodied the spirit of “banking with social engagement” and reinforced the Bank’s enduring role in nation-building beyond financial services.

بنگلہ دیش میں صحافیوں پر حملے اور گرفتاریاں ناقابل قبول، پریس کلب آف انڈیا کی شدید مذمت



عدالتی کارروائی کے طویل عرصے سے جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ پی سی آئی نے ان تمام صحافیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیادی

نئی دہلی: (پریس ریلیز) پریس کلب آف انڈیا نے بنگلہ دیش میں صحافیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد، میڈیا اداروں پر حملوں اور صحافیوں کی گرفتاریوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے معروف اخبارات پر ہجوم آلو اور دی ڈیلی اسٹار کے دفاتر پر پرتشدد حملے، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ بیان میں ایڈیٹر زکول کے صدر اور روزنامہ نیو ایج کے ایڈیٹر، سینئر صحافی نورل کبیر کو ہراساں کیے جانے کے واقعات پر بھی شدید تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا کے مطابق، بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک 100 سے زائد صحافیوں کو قتل کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے، جنہیں بغیر کسی

اساس ہوتی ہے اور میڈیا کو خاموش کرانے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ پریس کلب آف انڈیا نے واضح کیا کہ صحافیوں کے خلاف تشدد، دھمکیاں، حملے یا ہراساں نہ صرف میڈیا کی آزادی کے منافی ہیں بلکہ آئینی طور پر حاصل اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی بالادستی کی بھی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پریس کلب آف انڈیا کی صدر سنگیتا بارواہ پشاور کی اور سرکیری جزل افضل امام نے مطالبہ کیا کہ ان واقعات میں ملوث عناصر کی فوری نشاندہی کی جائے اور ایک منصفانہ، غیر جانبدار اور تیز رفتار تحقیقات کے ذریعے مجرموں کو قانون کے کنٹرول میں لایا جائے۔ پریس کلب آف انڈیا نے بین الاقوامی صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں صحافیوں کی سلامتی اور میڈیا کی آزادی کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔

انڈین مجلس فار سول رائٹس (IMCR) کے اعلیٰ سطحی وفد کی ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کئی مہمیں سے دہلی میں اہم ملاقات



نئی دہلی: انڈین مجلس فار سول رائٹس (IMCR) کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے آج نئی دہلی میں دراؤمنیئر اکٹوگم (DMK) کی سینئر رکن پارلیمنٹ محترمہ کئی مہمیں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات خوشگوار اور سنجیدہ ماحول میں ہوئی جس میں ملک کے موجودہ سماجی و سیاسی حالات، اقلیتی حقوق بالخصوص مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل، اور نیشنل ناڈو حکومت کی جانب سے ان مسائل کے تدارک میں اختیار کی گئی مثبت پالیسیوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وفد نے نیشنل ناڈو حکومت کی جانب سے مسلم مسائل کے حل میں سنجیدہ دلچسپی اور عملی اقدامات پر وزیر اعلیٰ ایم۔ کے۔ اسٹالن کی سنجیدہ کوششوں اور ان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا، خصوصاً وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اختیار کیے گئے وقف سے متعلق اقدامات کو سراہا، جن کے باعث ریاست میں اقلیتوں کو ایک محفوظ اور باوقار ماحول میسر آیا ہے۔ محترمہ کئی مہمیں سے وفد کی بات نہایت توجہ اور سنجیدگی سے سنی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈی ایم کے ہمیشہ آئینی اقدار، سیکولرزم اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم رہی ہے۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور ان کے جائز مسائل کو پارلیمنٹ اور متعلقہ فورمز پر مؤثر انداز میں اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ انڈین مجلس فار سول رائٹس کے صدر محمد ادیب نے اس موقع پر ملک کے موجودہ حالات اور خاص طور پر وقف املاک سے متعلق درپیش چیلنجز کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے وقف کے تحفظ اور اقلیتی حقوق کے سلسلے میں نیشنل ناڈو حکومت کے مثبت اور واضح موقف پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دیگر ریاستیں بھی اسی طرز پر آئینی ذمہ داریوں کو نبھائیں گی۔ ملاقات کے دوران IMCR کے نرشی اور خزانچی ایڈووکیٹ فیضیل احمد ایوینی اور سینئر صحافی انظر الباری بھی موجود تھے۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں جمہوری اداروں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ملک میں ہم آہنگی، انصاف اور سماجی توازن کو مضبوط کیا جاسکے۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ آئندہ بھی باہمی رابطہ اور تعاون جاری رکھا جائے گا اور مسلم کمیونٹی سمیت تمام اقلیتوں کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔

”نوائس آئی آر“ پر دہلی میں قومی کنونشن کا انعقاد شہریوں کے آئینی حق رائے دہی کے تحفظ پر دیا زور



درعیش موجودہ چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ ووٹر لسٹ، انتخابی طریقہ کار اور شہری شمولیت کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوتاہی عوام کے حق حکمرانی کو کمزور کرتی

نئی دہلی: شہری حقوق اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے سرگرم سول سوسائٹی تنظیموں کے پلیٹ فارم NO-SIR کے زیر اہتمام ”بالغ رائے دہی کے عالمی حق کے دفاع“ کے عنوان سے ایک اہم قومی کنونشن منعقد کیا گیا۔ اس کنونشن کا مقصد شہریوں کے آئینی حق رائے دہی کے تحفظ کو یقینی بنانا اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بعض اقدامات پر اٹھنے والے سنگین سوالات کو عوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا۔ کنونشن سے سابق جج صاحبان جسٹس مدن بی لوکور اور جسٹس اے کے پٹناجک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بالغ رائے دہی جمہوریت کی بنیاد ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی چھپر چھڑا آئینی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ انتخابی عمل میں

شفافیت، جوابدہی اور عوامی اعتماد کا تحفظ ناگزیر ہے۔ کنونشن میں ممتاز دانشور پروفیسر نوید تاملین اور معروف سماجی کارکن و ماہر معاشیات ژاں دریز نے جمہوریت کو

بنگلہ دیش دہکتی سیاست کے درمیان انتخابات اور تاریک ہوتا مستقبل!

کو خاموش کرانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آنے والا انتخابی عمل شفاف، آزاد اور قابل اعتماد نہیں رہے، بلکہ طاقتور ریٹیو کے زیر سایہ انجام پائے۔ بنگلہ دیش کی اس بگڑتی صورتحال پر بھارت کی تشویش بھی فطری ہے۔ نئی دہلی نے ہادی کے قتل سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی بد امنی اور حملوں پر سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت ہند کے پالیسی ساز حلقوں کو اندیشہ ہے کہ اگر تشدد بے قابو ہوا تو اس کے اثرات سرحد پار بھی پڑ سکتے ہیں، جن میں غیر قانونی نقل مکانی، سرحدی سلامتی کے مسائل اور خطے میں فرقہ وارانہ تناؤ کا پھیلاؤ شامل ہے۔ بنگلہ دیش کا عدم استحکام درحقیقت پورے جنوبی ایشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان تمام واقعات نے ایک بنیادی اور خوفناک سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا یہ تشدد محض اتفاقاً سیاسی بے چینی بھر ہے یا الیکشن کو مؤخر کرنے، کمزور کرنے یا نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی ایک منظم سازش ہے؟ سیاسی ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ جب انتخابات کے قریب آتے ہی تشدد، ادارہ جاتی بحران اور سماجی انتشار شدت اختیار کر جائے تو اسے محض اتفاق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو بنیاد بنا کر عام انتخابات میں تاخیر کا جواز پیدا کرنا یا ایک مخصوص سیاسی قوت کو ناگزیر حقیقت کے طور پر مسلط کرنا یہ دونوں امکانات واضح طور پر موجود ہیں۔ ان سب کے بیچ بھارت میں کانگریس کی پارلیمنٹ ششی تھرو کی صدارت میں قائم پارلیمانی کمیٹی نے بھی بھارت بنگلہ دیش تعلقات پر اپنی نو رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے بھی رپورٹ میں سیاسی عدم استحکام، سرحدی سلامتی اور تجارتی چیلنجز کو دو طرفہ تعلقات کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ علاوہ ازیں ڈھاکہ میں جاری سیاسی افراتفری، اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں اور بنگلہ دیش میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے تناظر میں بھارتی پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے حکومت ہند کو بھارت بنگلہ دیش تعلقات کے حوالے سے محتاط اور چوکنا رہنے کی واضح ہدایت دی ہے۔

نکال کر علاقائی محاذ آرائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تشدد کی اس آگ میں سب سے زیادہ اقلیتیں نشانہ بنتی اور جھڑپیں دھڑکی ہیں۔ ہجوم کے ہاتھوں اقلیتی طبقے کے ایک نوجوان کا بے رحمی سے قتل بنگلہ دیش کے اجتماعی ضمیر پر ایک بدنام اور کبھی نہ مٹنے والا داغ ہے۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اقلیتیں نشانہ بنتی ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ اقلیتوں پر ہونے والا تشدد نہ صرف آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ اسلامی اصولوں کی بھی صریح نفی ہے، جو جان کے احترام، مذہبی آزادی اور غیر مسلموں کے تحفظ کو



بنیادی قدر قرار دیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر کیا جانے والا تشدد درحقیقت اسلام دشمنی کا بدترین مظہر ہے۔ اور بنگلہ دیش کی مسلم عوام اس بات کو جتنی جلد سمجھ جائے تو بہتر ہے۔ اسی بد امنی کے تسلسل میں میڈیا ہاؤسز کے دفاتر پر حملے جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتے ہیں۔ آزاد صحافت کو خوفزدہ کرنا، خبروں کو دبانا اور صحافیوں کو نشانہ بنانا اس بات کا کھلا اور واضح ثبوت ہے کہ کچھ قوتیں سچ سے خائف اور ڈری ہوئی ہیں۔ انتخابات سے قبل میڈیا

ہونے والا انتخابی اتحاد محض سیاسی اشتراک نہیں بلکہ ایک نظریاتی طاقت کے ابھار کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ اتحاد ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریاست پہلے ہی کمزور، ادارے دباؤ میں اور معاشرہ شدید پولرائزیشن کا شکار ہے۔ ڈاکٹر یونس کی سرکار بے بس اور لاچار ہے۔ ان کے مطابق اس صف بندی کا نتیجہ عوامی فلاح کے بجائے تصادم، تقسیم اور سیاسی بلیک میلنگ کی صورت میں نکلنے کا خدشہ زیادہ ہے۔ اس پورے منظر نامے میں سب سے ہلا دینے والا واقعہ انقلابی تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کا قتل ہے، جس نے بنگلہ دیش کو ایک



منے تشدد کے دور میں داخل کر دیا۔ ایک سیاسی ریلی کے دوران ہونے والا یہ قتل صرف ایک شخص کی ہلاکت نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اختلاف رائے اب جان لینے تک جا پہنچا ہے۔ اس قتل کے بعد ملک میں بھڑکے بے قابو تشدد نے ثابت کر دیا کہ ریاستی گرفت کمزور ہو چکی ہے اور ہجوم قانون کی جگہ لے رہا ہے۔ تشویش کا بات یہ بھی ہے کہ بعض گروہوں نے ہادی کے قاتلوں کو بھارت پر پناہ دینے کا الزام ڈھ کر معاملے کو اندرونی سیاست سے

پڑوسی ملک میں زبردست احتجاجی مظاہرے کے بعد بنگلہ دیش کی سابق معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بڑی سیاسی تبدیلی کے بعد ملک چھوڑ کر بھارت آنا پڑا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید حالات اب بہتر ہو جائیں گے مگر محض ایک سال کے اندر ہی بنگلہ دیش تاریخ کے سب سے نازک، انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن موڑ پر ایک بار پھر آکھڑا ہے، جہاں سیاست، تشدد، مذہب، طلبا تحریک اور علاقائی طاقتوں کے مفادات ایک دوسرے سے اس طرح مدغم ہو چکے ہیں کہ یہاں کا مستقبل انتہائی تاریک اور حال خوفناک و ڈراؤنا دکھائی دیتا ہے۔ انتخابات کی تاریخوں کے اعلان نے بظاہر جمہوری عمل کو متحرک ضرور کیا ہے، تاہم زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ انتخابی اعلان استحکام کا نہیں بلکہ بد امنی، افراتفری اور منظم انتشار کے ایک نئے مرحلے کا پیش خیمہ بنتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ انتخابی اعلان کے فوراً بعد سیاسی قوتوں کی غیر معمولی صف بندی بالخصوص جماعت اسلامی کے زیر قیادت دیگر مسلم جماعتوں کے اتحاد اور طلباء گروہ کے انقلابی منچ نے واضح کر دیا کہ یہ محض اقتدار کی پرامن منتقلی کا مرحلہ نہیں، بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور ریاستی اداروں پر کنٹرول کی ایک ہمہ گیر جنگ ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی جارحانہ واپسی نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ طلبہ گروہوں کا خود کو ایک انقلابی قوت کے طور پر پیش کرنا اور براہ راست انتخابی سیاست میں داخل ہونے کا اعلان بظاہر جمہوری حق کے دائرے میں ضرور آتا ہے، مگر جب یہی گروہ تشدد، توڑ پھوڑ، لوٹ پاٹ، آگ زنی، انساںوں پر حملے، ریاستی اداروں سے تصادم اور عوامی جان و مال کے نقصان سے جڑا ہوا تو یہ سوال ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آیا یہ سیاست ہے یا ریاست کو ریغمال بنانے کی ایک منظم کوشش۔ اسی دوران مذہبی و سیاسی اتحاد کی تشکیل نے بنگلہ دیش کی سیاست کو ایک اور خطرناک رخ کی طرف موڑ دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ اٹھ مسلم جماعتوں کے درمیان قائم